ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**
**DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA**
**STARRED QUESTION NO.211**
**TO BE ANSWERED ON THE 16TH MARCH, 2021**
**NEW MEDICAL COLLEGES IN KARNATAKA**

**211 SHRI IRANNA KADADI:**

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

(a) whether Government has decided the locations/places to set up new medical colleges in Karnataka, if so, the details thereof;

(b) the number of intake capacity in each of these new medical colleges that have been proposed to be set up in Karnataka;

(c) the details of the funds earmarked for opening these medical colleges in Karnataka;

(d) whether Government had held any review meeting in this regard to oversee the establishment of new medical colleges recently; and

(e) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor?

**ANSWER**
**THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**
**(DR. HARSH VARDHAN)**

(a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 211* FOR 16TH MARCH, 2021**

**(a) to (e)** The Ministry of Health & Family Welfare administers a Centrally Sponsored Scheme for "Establishment of new medical colleges attached with existing district/referral hospitals". Under Phase-III of the Scheme, four medical colleges have been approved in Karnataka in the year 2019-20 to be established at Chikkamagaluru, Haveri, Yadgiri and Chikkaballapura with intake capacity of 150 MBBS seats each. The medical colleges have been approved at a cost of Rs.325 crore each to be shared between Centre and State Government of Karnataka in the ratio of 60:40. The details of release of funds are as under:-

(Rs. in crore)

| S. No. | District | Approved Cost | Central Share | Central share released as on date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikkamagaluru | 325 | 195 | 50 |
| 2 | Haveri | 325 | 195 | 60.64 |
| 3 | Yadgiri | 325 | 195 | 50 |
| 4 | Chikkaballapura | 325 | 195 | 50 |

Further, meetings with the States are held at various levels at regular intervals to monitor the progress of the medical colleges in terms of construction, utilization of funds and plan of the States to make the colleges functional.

******

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या: 211**
**16 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**कर्नाटक में नये चिकित्सा महाविद्यालय**

***211 श्री इरण्ण कडाडिः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए स्थलों/स्थानों का निर्धारण कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कर्नाटक में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित इन चिकित्सा महाविद्यालयों में कितने-कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा;
(ग) कर्नाटक में इन चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना पर निगरानी रखने के लिए इस संबंध में हाल ही में कोई समीक्षा बैठक की थी; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन)**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

16 □□□, 2021 □□□□□ □□ज□ □□□ □□□□ि□□ प्रश्न □□211 के उत्तर म उल्लिखित □□□□□

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'वतमान जिला/ रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए कद्रीय प्रायोजित योजना संचालित करता है। योजना के चरण-III के तहत, चिकमगलुरु, हावेरी, यादगिरि और चिक्काबल्लापुरा म प्रत्येक म 150 एमबीबीएस सीटों की दाखिला क्षमता के साथ स्थापित किए जाने हेतु वष 2019-20 म कनाटक म चार मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए ह। इन मेडिकल कॉलेजों का अनुमोदन प्रत्येक कॉलेज के लिए 325 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया गया और यह लागत कद्र तथा कनाटक राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात म साझा की जानी है। निधियां निगत करने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु.)

| क्र.□□ | □□□□ | □□□ि□□ □□□□ | कद्र □□ □□स□□ | □□ □ी □□□□□ □□ निगत किया गया कद्र □□ □□स□□ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चिकमगलुरु | 325 | 195 | 50 |
| 2 | हावेरी | 325 | 195 | 60.64 |
| 3 | यादगिरी | 325 | 195 | 50 |
| 4 | चिक्काबल्लापुरा | 325 | 195 | 50 |

इसके अलावा, कॉलेजों को प्रचालनरत करने के लिए निमाण, निधियों के उपयोग तथा राज्यों की योजना के संदभ म मेडिकल कॉलेजों की प्रगति की मॉनीटरिंग करने हेतु नियमित अंतरालों म राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठक आयोजित की जाती ह।

*****

**श्री इरण्ण कडाडिः** उपसभापति महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कर्णाटक की जनसंख्या सात करोड़ से अधिक है और हमारा प्रदेश केन्द्र सरकार को राजस्व प्रदान करने में तीसरे स्थान पर है, लेकिन आज भी वहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के माध्यम से कर्णाटक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस दिशा में अभी तक सरकार ने क्या काम किया है?

**श्री उपसभापति**: धन्यवाद। आप सवाल संक्षेप में पूछिए। माननीय मंत्री जी।

**डा. हर्ष वर्धनः** सर, माननीय सदस्य ने हम सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यद्यपि देश में अभी तक 22 एम्स हैं, जिसमें से 16 पिछले सात साल में ही कन्सीव होने के बाद विभिन्न डेवलपमेंट के स्टेजेज़ में हैं, वे प्लान हुए हैं, लेकिन कर्णाटक के अंदर अभी कोई "एम्स" डेवलप नहीं हुआ है। वहां के मुख्य मंत्री ने और वहां के लीडर्स ने निश्चित रूप से हम लोगों को इससे पहले भी रिक्वेस्ट भेजी थी। स्वास्थ्य विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इस विषय पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और जैसे ही इस योजना को फाइनलाइज़ किया जाएगा, उसकी घोषणा निश्चित रूप से बजट वगैरह में होगी, तभी हम उसके बारे में औपचारिक रूप से कह पायेंगे, लेकिन यह विषय हमारे संज्ञान में है।

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंटरी। कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री भी संक्षेप में उत्तर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका मिल सके।

**श्री इरण्ण कडाडिः** सर, मेरा दूसरा प्रश्न बेलगावि जिले से संबंधित है। बेलगावि वैदिकीय विज्ञान संस्थान में प्रतिदिन कर्णाटक, महाराष्ट्र और गोवा से बहुत मरीज आते हैं, लेकिन यहां पर एक

व्यवस्थित कैंसर अस्पताल नहीं होने के कारण मरीजों को बहुत असुविधा हो रही है। कैंसर के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या कैंसर के बढ़ते हुए मामलों के उपचार के लिए सरकार कैंसर संस्थान खोलने के बारे में विचार कर रही है?

**डा. हर्ष वर्धनः** सर, कैंसर के उपचार के लिए dedicatedly कैंसर कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम है, उसके तहत देशभर में भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कैंसर सेंटर्स और दूसरे सेंटर्स को क्रिएट करती है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, लेकिन किसी भी स्थान पर उसको डेवलप करने के लिए, जो बेसिक योजना होती है, उसका प्लान बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को ही देना होता है। मेरा माननीय सदस्य से यह कहना है कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से विषय को pursue करके अगर वे किसी भी योजना के तहत, किसी भी स्कीम में भारत सरकार के पास एप्रोच करेंगे, तो भारत सरकार निश्चित रूप से उसको positively देखेगी।

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद। माननीय श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली।

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, the Andhra Pradesh Government is on a mission to strengthen public hospitals and reduce medical expenditure burden on the poor. The Government is going to sanction 16 medical colleges across the State; out of which, three colleges have already been sanctioned by the Government of India. I would like to know from the hon. Minister: Does the Government propose to provide financial support for the remaining 13 colleges?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, in fact, in the second tenure of Prime Minister, Narendra Modiji, the Government has sanctioned 75 new medical colleges in various States of India. These are preferably in the aspirational districts or in the districts where the most deprived and the downtrodden people live and where there is no medical college either in the Government or the private sector. All these 75 colleges across various

States in the country, they have been finalized. They have been notified. The State Governments have been informed and the Government of India supports 60 per cent of the budget expenditure on these medical colleges.

**श्री नरहरी अमीन** : माननीय उपसभापति महोदय, क्या केंद्र सरकार सभी राज्यों के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में medical colleges शुरू करने की सोच रही है, अगर यह उत्तर हाँ में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने सालों के अंदर सभी राज्यों के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में medical colleges शुरू हो सकते हैं?

**डा. हर्ष वर्धन** : उपसभापति जी, देश में इस समय भी, 2014 onwards, 157 medical colleges, development की विभिन्न stages में हैं। इनमें phase-1 में 58 हैं , phase-2 में 24 हैं और जैसा कि मैंने अभी उत्तर दिया है कि हमने phase-3 में और 75 medical colleges घोषित किए हैं। देश में 2014 तक एमबीबीएस की 50 हज़ार सीट्स थीं, परंतु इसके परिणामस्वरूप पिछले 6-7 सालों में 30 हज़ार सीट्स और add हुई हैं। अभी जब ये medical colleges develop होंगे, तब इनसे और सीट्स add होंगी। इसके साथ-साथ जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, चूंकि इसकी भी सदन ने स्वीकृति दी थी, अतः वह भी इस विषय पर और गंभीरता से विचार कर रहा है, assessment भी कर रहा है कि आने वाले वर्षों में देश को और कितनी सीट्स की या और कितने medical colleges की आवश्यकता है। जैसे-जैसे हमें नेशनल मेडिकल कमीशन की recommendations मिलेंगी, वैसे-वैसे सरकार निश्चित रूप से उनके अनुरूप आवश्यकतानुसार अपनी योजनाएं बनाएगी और आपके सामने प्रस्तुत करेगी।